



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]
No. 157]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 1995/चैत्र 15, 1917
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 1995/CHAITRA 15, 1917

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1995
(आयकर)

सा.का.नि. 331(अ.).—चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवंचन को नोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित करार, उक्त करार के अनुच्छेद-28 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए दोनों ही संबिदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात् माह नवम्बर, 1994 के 21 वें दिन से प्रवृत्त हो गया है :

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारतसंघ में लागू किए जाएंगे ।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार
और

चीन लोक गणराज्य की सरकार
के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन लोक गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक करार सम्पन्न करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद—1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो उक्त संबिदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद—2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह करार किसी संबिदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उपभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय पर लगाए

गए करों पर लागू होगा भले ही ये किसी भी तरह से लगाए जाएं।

2. कुल आय अथवा चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाषा/पूँजीगत वृद्धि पर करों सहित अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर करों के रूप में माना जाएगा।

3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :

(क) भारत में,

आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधि-भार भी शामिल है;

(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा)

(ख) चीन में,

(i) व्यक्ति आयकर;

(ii) विदेशी निवेश वाले उद्यमों तथा विदेशी उद्यमों के लिए आयकर;

(iii) स्थानीय आयकर;

(जिसे इसके बाद "चीनी कर" कहा जाएगा)।

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा मारमः इसी तरह के करों पर लागू होगा, जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात्, पैराग्राफ 3 में उल्लिखित मौजूदा करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में ऐसे परिवर्तन करने के बाद, एक उचित अवधि के अन्दर एक-दूसरे को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद—3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों :—

(क) "भारत" पद से अभिप्रेत है—भारत गणराज्य का प्रदेश तथा उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों;

(ख) "चीन" पद से अभिप्रेत है—चीन लोक गणराज्य : जब यह भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त होगा, तब इसमें अभिप्रेत है—चीन लोक गणराज्य का समस्त प्रदेश जिसमें इसका राज्य क्षेत्रीय समुद्र भी शामिल है जिस पर कराधान से संबंधित चीन के कानून लागू होते हों, तथा इसके

राज्य क्षेत्रीय समुद्र से परे कोई क्षेत्र जिस पर समुद्र तथा समुद्री शक्ति जागृत क्षेत्रों तथा समाधनों की खोज करने तथा इनका उपयोग करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार चीन गणराज्य के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार हों;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार चीन अथवा भारत अभिप्रेत है;

(घ) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार "चीनी कर" अथवा "भारतीय कर" अभिप्रेत है;

(ङ) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी और कोई अन्य सन्ता शामिल है, जिसे संवर्धित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत एक कराधेय इकाई माना जाता हो,

(च) "कम्पनी" पद से कोई ऐसी निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सन्ता अभिप्रेत है जिस कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय माना जाता हो;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है—किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति और कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारों अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो;

(झ) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है—किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी, किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

(ञ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से चीन के मामले में, कराधान संबंधी राज्य प्रशासन अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अभिप्रेत है।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें

परिभाषित नहीं हुआ हो जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य के उन करों में संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद—1

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” पद में अभिप्रेत है—कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस संविदाकारी राज्य में उसके कानूनों के अनुसार उस के अधिवास, निवास, मुख्यालय के स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगता हो।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसकी हैसियत निम्नानुसार निश्चित की जाएगी :

- (क) उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास उपलब्ध हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);
- (ख) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास नहीं हो, तो उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;
- (ग) यदि आदतन दोनों ही संविदाकारी राज्यों में उसके रहने का स्थान हो अथवा उनमें से किसी में भी नहीं हो, तो उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;
- (घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं हो, तब संविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका मुख्यालय स्थित है।

अनुच्छेद—5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, “स्थायी संस्थापन” पद में कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके

द्वारा उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. “स्थायी संस्थापन” पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबन्ध का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना;
- (ङ) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआं, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्ष का कोई अन्य स्थान;
- (छ) कोई भाण्डागार, ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में जो दूसरों के लिए भंडारण सुविधाएं मुहैया करता हो;
- (ज) कोई फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, बानिकी, बागवानी अथवा तत्संबंधी कार्य किए जाते हों;
- (झ) कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण अथवा संदोहन के लिए किया जाता है परन्तु यह तभी होगा यदि इनका प्रयोग 183 दिनों से अधिक की अवधि के लिए किया जाए;
- (ञ) कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण कार्य, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उसमें संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप जहां ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप, (ऐसे अन्य स्थलों, परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों यदि कोई हों सहित) 183 दिनों से अधिक तक की अवधि के जारी रहते हों;
- (ट) एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में कर्मचारियों अथवा अन्य कामियों के माध्यम से, अनुच्छेद 12 (रायल्टियां तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस) में वर्णित तकनीकी सेवाओं से भिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना, परन्तु ऐसा तभी होगा यदि इसी तरह के कार्य-कलाप दूसरे संविदाकारी राज्य में कुल मिलाकर 183 दिनों की अवधि अथवा अवधियों के लिए जारी रहते हों।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, “स्थायी संस्थापन” पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- (क) उद्यम के भाग अथवा पण्य-वस्तुओं के केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा छिपीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;

(ख) केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखना;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखना;

(घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं को केवल खरीदने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;

(ङ) उद्यम के लिए केवल किसी अन्य दूसरे कार्यकलाप के प्रयोजनार्थ कारोबार का एक निश्चित स्थान रखना, जो तैयारी संबंधी अथवा सहायक स्वरूप का हो।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के एजेंट से भिन्न कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है, किसी संविदाकारी राज्य में, दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम की ओर से कार्य करता है तथा उसके पास उद्यम की ओर से संविदाएं निष्पन्न करने के लिए प्राधिकार है और वह आदतन अपने इस प्राधिकार का प्रयोग करता है, तो उस उद्यम के संबंध में यह माना जाएगा कि उसका ऐसे किसी कार्यकलापों के संबंध में प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन है जो वह व्यक्ति उक्त उद्यम के लिए करता है, यदि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप पैरा 3 में उल्लिखित उन कार्यकलापों तक सीमित न हों जिनकी वजह से, यदि उन्हें कारोबार के किसी निश्चित स्थान के जरिए किया गया हो, उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार का यह निश्चित स्थान स्थायी संस्थापन नहीं बनेगा।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होता नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी बलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। लेकिन, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तब उसे इस पैराग्राफ के अधिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैसियत का कोई एजेंट नहीं समझा जाएगा।

6. यदि कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती अथवा किसी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कंपनी को स्वतः ही दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जायेगा।

अनुच्छेद—6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अन्तर्गत होता है, जहां उक्त सम्पत्ति स्थित हो। किसी भी स्थिति में, इस पद में यह शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के उपांग के रूप में सम्पत्ति, कृषि और बानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति के विषय में सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हो, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भंडार स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिये अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार। जलयान तथा विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जायेंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिये प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद—7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जायेगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है। किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उस उद्यम को उत्पन्न हुए माने जायें।

तथापि, इस पैराग्राफ के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि उद्यम यह सिद्ध करे कि स्थायी संस्थापन द्वारा उपर्युक्त क्रियाकलाप कर पाना संभव नहीं हो पाता अथवा इनका स्थायी संस्थापन से कोई संबंध नहीं है।

2. पैराग्राफ 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से

कारोबार करता हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभों को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जायेगा जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या उससे मिलने-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतन्त्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. जहाँ तक किसी संविदाकारी राज्य के कर कानून में किसी एक विशिष्ट व्यावसायिक क्रियाकलाप के संबंध में किसी स्थायी संस्थापन को समझे जाने वाले लाभों का, समझे गये लाभ के रूप में निर्धारण करने की व्यवस्था है, वहाँ पैराग्राफ 2 में कुछ भी संविदाकारी राज्य को कानून के इन उपबन्धों को लागू करने से वंचित नहीं करेगा बशर्ते कि परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुसार हो।

4. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करते में, उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जायेगी जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ खर्च किये जाते हैं तथा जिनमें इस प्रकार खर्च किये गये कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होते हैं, भले ही ये उस राज्य में खर्च किये गये हों, जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा ये अन्यत्र किये गये हों तथा ये उस राज्य के कर कानून के उपबन्धों के अनुसार किये गये हों।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जायेगा कि उस स्थायी संस्थापन ने, उद्यम के लिये माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी है।

6. पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 5 के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

7. जहाँ लाभों में आर की वे सदैव शामिल हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबन्ध इस अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद-8

जहाजरानी तथा वायु परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम, जो वहाँ का निवासी हो, द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जायेगा।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों का तात्पर्य किसी उद्यम द्वारा पैराग्राफ 1 में उल्लिखित क्रमशः समुद्र अथवा वायुमार्ग वाले जलयान अथवा वायुयान के स्वामियों अथवा पट्टारों अथवा चार्टरिंग द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल के परिवहन से प्राप्त लाभों से होगा और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) ऐसे परिवहन के लिये टिकटों की बिक्री;

(ख) ऐसे परिवहन से सम्बद्ध जलयानों अथवा विमानों का किराया; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में परिवहन के संबंध में आधानों (आधानों के परिवहन के लिये ट्रेलरों, बर्गेज तथा सम्बद्ध उपकरण सहित) के प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराये से प्राप्त आय।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा विमानों के परिचालन से प्रत्यक्षता संबंधित निधियों पर व्याज को इस अनुच्छेद में वर्णित लाभों के रूप में माना जायेगा, तथा अनुच्छेद 11 (व्याज) के उपबन्ध ऐसे व्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

4. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध किसी पूल, किसी संयुक्त-कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन एजेंसी के भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-9

सहयोगी उद्यम

1. जहाँ

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण, अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं; और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतन्त्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, जहाँ ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभों में शामिल किये जा सकेंगे और उन पर अनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहाँ एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार के लाभों को सम्मिलित करता है जो प्रथमोक्त राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें इस तरह की होती जो स्वतन्त्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब दूसरा राज्य उन लाभों पर वहाँ प्रभावी कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में, इस करार के अन्य उपबन्धों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के समक्ष प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद-10

लाभांश

1. संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये लाभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, उसी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी-स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांश की सकल रकम का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस पैराग्राफ के उपबन्धों का प्रभाव उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान पर नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय में है, जो लाभों की भागीदारी के ऋण-दावे नहीं हैं और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय में है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी-स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार करता है जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी, वहाँ स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से निवासी है, यथा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान में स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाएं करती है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की

अदायगी की जाती है, वहाँ वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान में प्रभावी रूप से सम्बद्ध है, ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 11, जैसी भी स्थिति हो, के उद्देश्य लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ वह दूसरा संविदाकारी राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहाँ तक किसी भी प्रकार का कर नहीं लगायेगा जहाँ तक कि ऐसा लाभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने हो अथवा जहाँ तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वहाँ उस संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थापित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान में प्रभावी रूप से संबंधित है, वहाँ उस दूसरे राज्य में कम्पनी के अतिरिक्त लाभों पर अतिरिक्त लाभ संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों हों।

अनुच्छेद-11

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य से उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा, जिस संविदाकारी राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभागी-स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर व्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, किसी राजनैतिक उप-प्रभाग, किसी स्थानीय प्राधिकरण और उसके मंत्रालय बैंक अथवा उस सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले किसी वित्तीय गन्थान अथवा उस अन्य संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित ऋण-दावों के संबंध में उस दूसरे संविदाकारी राज्य को किसी दूसरे निवासी द्वारा, किसी राजनैतिक उप-प्रभाग, किसी स्थानीय प्राधिकरण और उसके मंत्रालय बैंक अथवा उस सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले किसी वित्तीय संस्थान द्वारा प्राप्त व्याज को प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर में मुक्त रखा जाएगा।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "व्याज" शब्द से अभिप्रेत है—प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावा से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और चाहे

उन्हें ऋण-दाना के लक्ष्यों में भारीवारी का कोई अधिकार प्राप्त हो सकता है। जो और विशेष रूप से सरकारी प्रति-भूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्तों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसे प्रतिभूतियों, बंधपत्तों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और परस्कार शामिल हों। देरी से को जाने वाली अदायगी के लिए अर्थदण्ड को इस अनु-च्छेद के प्रयोजन के लिए व्याज की रूप में नहीं माना जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि व्याज का हितभागी-स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारगर करना हो अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करना हो और जिस ऋण-दावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

6. व्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ अभी माना जाएगा, जब व्याज अदा करने वाली उस संविदाकारी राज्य की सरकार, उस संविदाकारी राज्य का कोई राजनीतिक उप-भाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो। किन्तु, जहाँ व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है जिसके संबंध में ऋण अदा किया गया था, जिस पर व्याज की अदायगी की जाती है, और उस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वसूल किया जाता है, तो इस प्रकार का व्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ व्याज अदाकर्ता तथा हितभागी-स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई व्याज की रकम, उस ऋण दावे का ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए व्याज को रकम अदा की गई है, उस रकम से कम जाना है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी-स्वामी के बीच सहमति हो गई होनी, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अनिवार्य भाग पर, उस तारीख के अन्त्य उपबंध का सम्बन्ध अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद—12

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उन संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि प्राप्ति रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हित-भागी-स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी भी कॉपीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, जिनमें सिनेमा-फिल्में, टेलीविजन के संबंध में उपयोग में आने वाली फिल्में अथवा वीडियो टेपे अथवा रेडियो प्रसारण के गैर-ध्वनि के लिए टेपे भी शामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा मोडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" शब्द से अभिप्रेत है—किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रबन्धकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं की व्यवस्था के लिए कोई भुगतान, लेकिन इसमें करार के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 2(ट) और अनुच्छेद 15 में उल्लिखित कार्य-कलापों के लिए अदायगी शामिल नहीं है।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी-स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहाँ पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारगर करना है अथवा उस दूसरे राज्य में वहाँ पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, तथा जिस अधिकार, सम्पत्ति अथवा संविदा के संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।

6. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदाकर्ता उस संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस संविदाकारी राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने का वचन दिया गया हो और ऐसी रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अदाकर्ता और हितभागी-स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम, इसके उपयोग, अधिकार अथवा सूचना जिसके लिए इसकी अदायगी की गई थी, उस रकम से बढ़ जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा हित-भागी-स्वामी के बीच महमति हुई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग, इस करार के अन्य उपबंधों को देखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा।

अनुच्छेद—13

पूँजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि अन्तरणकर्ता निवासी है।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूँजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित किसी सम्पत्ति से भिन्न, किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली किसी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद—14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी :—

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है;

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संबंधित कराधेय वर्ष में, कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक हों, तो यथा-स्थिति के अनुसार उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती है।

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, बर्कालों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद—15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी

निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, बशर्ते कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहाँ में प्राप्त है, उस पर, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

- (क) प्राप्तकर्ता संबंधित कराधेय वर्ष में ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं है; और
- (ख) पारिश्रमिक ऐसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से चुकाया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
- (ग) पारिश्रमिक जो ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोजक का दूसरे संविदाकारी राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, द्वारा प्राप्त संचालित पोत अथवा विमान पर दिये गये नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका यह उद्यम एक निवासी है।

अनुच्छेद-16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैमियत में प्राप्त की गई हों, उन पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे

संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहाँ किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैमियत से किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहाँ उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से अर्जित आय को, या तो संविदाकारी राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के भाग के रूप में अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों में अथवा किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण में सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से समर्थित होते हैं, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर में मुक्त रखा जा सकेगा।

अनुच्छेद-18

पेंशन

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन, एक संविदाकारी राज्य के निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अर्दा की गई पेंशन, वार्षिकी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस संविदाकारी राज्य की सामाजिक सुरक्षा पद्धति की किसी ऐसी सार्वजनिक योजना के अंतर्गत अर्दा की गई पेंशनों, वार्षिकियों और इसी प्रकार के अन्य भुगतानों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद-19

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य की सरकार, उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में सरकारी स्वरूप के कार्यों को पूरा करने के लिए अर्दा किए गए पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, जो:

- i) उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा
- ii) मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य की सरकार, उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित कोष द्वारा उसमें से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उस संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तब लगेगा, यदि व्यक्ति उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध, किसी संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद-20

प्रोफेसर्स, अध्यापकों और अनुसंधान-छात्रों द्वारा प्राप्त की गई अदायगियां

1. कोई व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी था और प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था अथवा अनुसंधान संस्था में शिक्षण, व्याख्यान देने अथवा अनुसंधान करने के मूल प्रयोजन के लिए प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में मौजूद है, पर ऐसे शिक्षण, व्याख्यान देने अथवा अनुसंधान के लिए पारिश्रमिक के लिए प्रथमोल्लिखित राज्य में पहली बार आगमन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद अनुसंधान में प्राप्त उस आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा अनुसंधान मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो।

अनुच्छेद-21

विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों और प्रशिक्षकों द्वारा प्राप्त की गई अदायगियां

1. किसी विद्यार्थी, व्यावसायिक प्रशिक्षु अथवा प्रशिक्षणार्थी, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा, प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उसके द्वारा अपने रख-रखाव, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्राप्त की गई अथवा व्युत्पन्न की गई निम्नलिखित अदायगियों अथवा आय पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर से छूट होगी:

(क) उसके भरण-पोषण, शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस संविदाकारी राज्य के बाहर के स्रोतों से प्राप्त की गई अदायगियां;

(ख) सरकार अथवा किसी वैज्ञानिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य कर से छूट प्राप्त संगठन द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों, छात्रवृत्तियों अथवा पुरस्कारों; और

(ग) भरण-पोषण के प्रयोजन के लिए उस संविदाकारी राज्य में निष्पादित व्यक्तिगत सेवाओं से प्राप्त आय।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो, परन्तु किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रत्यक्षतः पहुंचाने की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे।

अनुच्छेद-22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-वहीं वे अर्जित होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा परिभाषित अचल संपत्ति से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा संपत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मरौं पर, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में अद्भुत होती हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद—23

दोहरे कराधान को दूर करने के तरीके

6. चीन में निम्नलिखित प्रकार के दोहरे कराधान को दूर किया जाएगा :

(क) जहां पर चीन का कोई निवासी भारत में आय प्राप्त करता है, इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में देय आय पर कर की राशि उस निवासी पर लगाए गए चीनी कर के प्रति क्रेडिट की जा सकती है। तथापि, क्रेडिट की राशि चीनी कराधान कानूनों और विनियमों के अनुसार परिकल्पित आय पर चीनी कर की राशि से अधिक नहीं होगी :

(ख) जहां पर भारत से प्राप्त की गई आय भारत की किसी निवासी कम्पनी द्वारा चीन की निवासी कम्पनी को अदा किया गया लाभांश हो और जो लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के कम से कम 10 प्रतिशत शेयर रखती हो, कम्पनी अपनी आय के संबंध में लाभांश अदा करने वाली कम्पनी द्वारा भारत में अदा किया गए कर को क्रेडिट देते समय शामिल करेगी।

2. भारत में, दोहरे कराधान को निम्नलिखित प्रकार में रोका जाएगा :

जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार चीन में कर लगेगा, वहां भारत, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती के द्वारा उस निवासी की आय पर चीन में अदा की गयी आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा। तथापि, ऐसी कटौतियाँ, आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होंगी (कटौती दिए जाने से पूर्व यथा संगणित) जिन पर चीन में आय पर, जैसा भी मामला हो, कर लगाया जा सकेगा।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 में उल्लिखित संविदाकारी राज्य में अदा किए गए कर में वह कर भी शामिल समझा जाएगा जो कि देय होता परन्तु आर्थिक विकास के लिए संविदाकारी राज्यों के कर कटौती, छूट अथवा अन्य कर प्रोत्साहनों से संबंधित कानूनी उपबंधों के कारण देय नहीं है।

अनुच्छेद—24

सम-अवधार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी

ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर एक समान परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू को जानी हो।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक-समान परिस्थितियों में अथवा एक-समान शर्तों के अधीन समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।

3. जहां पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी संस्थापन के लाभों पर एक संविदाकारी राज्य के द्वारा उस दर पर कर लगाया जाता है जो कि प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के ऐसे ही उद्यम के लाभों पर लगाए गए कर से भिन्न है, तो इसे अनुच्छेद के अंतर्गत पक्षपात पूर्ण नहीं समझा जाएगा।

4. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को किसी सिविल स्तर अथवा किन्हीं पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कर प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्तिगत छूट, राहत और कटौतियाँ प्रदान करे जो कि वह अपने निवासियों को प्रदान करता है।

5. जहां पर अनुच्छेद 9 का पैरा 1, अनुच्छेद 11 का पैरा 7 अथवा अनुच्छेद 12 का पैरा 7 के उपबंध लागू होते हैं, को छोड़कर, किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को ऐसे उद्यम के कराधान लाभों का पता लगाने के प्रयोजन के लिए अदा किया गया व्याज, राशिदियाँ और अन्य भुगतान पर उन्हीं शर्तों के तहत कटौती दी जाएगी जिस प्रकार संविदाकारी राज्य के देशीय कानूनों के उपबंधों के तहत प्रथमोल्लिखित राज्य के निवासी को अदा करने पर दी जाती है।

6. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में वैसी ही परिस्थितियों और वैसी ही शर्तों के अधीन ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है।

7. इस अनुच्छेद में “कराधान” पद का अर्थ उन्हीं करों से होगा जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद—25

पारिवारिक करार विधि

1. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के तहत आता हो तो यह उस संविदाकारी राज्य को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणाम-स्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह किसी संतोषजनक हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्य के स्वदेशी कानूनों में कोई समय-सीमा क्यों न हो।

3. यदि इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयाँ अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के उपकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. पैराग्राफ 2 और 3 के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जहाँ समझौता करने की दृष्टि से उपयुक्त हो, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधि मौखिक विचार विमर्श के लिए आपस में मिल सकते हैं।

अनुच्छेद—26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस

करार के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं जहाँ तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था करार के प्रतिकूल नहीं हो ताकि विशेष रूप से ऐसे करों के अपवर्जन को रोका जा सके। सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल है) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हो जिन पर यह लागू होता हो। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे। वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबार संबंधी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसका प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्थिक पब्लिक) के अनुकूल हो।

अनुच्छेद—27

राजनयिक एजेंट तथा कांसुली अधिकारी

इस करार की किसी भी बात से राजनयिक एजेंटों अथवा कांसुली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद—28

प्रवर्तन

इस करार को लागू करने के लिए प्रत्येक देश में आवश्यक आन्तरिक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने की राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान की तारीख के तीसरे दिन को यह करार लागू होगा। यह करार इस प्रकार लागू होगा।

- (क) भारत में, इस करार के लागू होने वाले कैलेंडर वर्ष के बाद वाले अप्रैल मास के प्रथम दिन अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ;
- (ख) चीन में, इस करार के लागू होने वाले कैलेंडर वर्ष के बाद वाले जनवरी मास के प्रथम दिन की अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कराधेय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में।

अनुच्छेद—29

समापन

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा परन्तु दोनों में से कोई भी सविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष में जून मास की तीस तारीख को या उससे पहले राजनयिक माध्यम से लिखित रूप से करार के समापन की सूचना दूसरे सविदाकारी राज्य को देसकता है। ऐसी परिस्थिति में यह करार निष्प्रभावी हो जाएगा।

- (क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के पहले दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में।
- (ख) चीन में, जिस कैलेंडर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी मास के पहले दिन अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले कराधेय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में।

जिसके माध्यम में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ चौरानवें के जुलाई मास के अठारहवें दिन हिन्दी, चीनी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया तथा तीनों पाठ

समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से चीन लोक गणराज्य की सरकार की ओर से

प्रोतीकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए चीन लोक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार (जिसे इसके पश्चात् “करार” कहा जाएगा) पर हस्ताक्षर हो जाने पर दोनों पक्ष निम्नलिखित व्यवस्थाओं पर सहमत हो गए हैं जो कि इस करार के अनिवार्य भाग हैं ;

1. अनुच्छेद 3 पैरा 1 उप-पैरा घ के संदर्भ में ;

यह समझा जाता है कि “कर” पद में उस दण्ड को शामिल नहीं किया जाएगा जो कि उन करों, जिन पर वह करार लागू होता है, से संबंधित कानूनों और विनियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में लगाया जाता है।

2. अनुच्छेद 8 के संदर्भ में इन पर भी छूट लागू होगी:

- (i) भारत में, चीन में व्यवसाय कर जैसा कोई कर जो करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् भारत में लगाया जाता है ;
- (ii) चीन में व्यवसाय कर।

3. अनुच्छेद 26 के संदर्भ में ;

दोनों सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों के संबंध में सहमत होते रहेंगे जो कि नेमी आधार पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे।

जिसके माध्यम में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतीकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ चौरानवें के जुलाई मास के अठारहवें दिन हिन्दी, चीनी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया तथा तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से चीन लोक गणराज्य की सरकार की ओर से
मनमोहन सिंह श्री क्वियन क्वियिन)

[अधिसूचना सं. 9747/95-फा. सं. 503/5/93-एफ.टी.डी.]

जी. श्री. श्री निवानन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 1995

INCOME-TAX

G.S.R. 331(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on the 21st day of November, 1994 after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said Agreement in accordance with Article 28 of the said Agreement ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
ANDTHE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA

FOR THE

AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China.

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

Have Agreed as follows :

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are :

- (a) in China :
 - (i) the individual income tax ;
 - (ii) the income tax for enterprises with foreign investment and foreign enterprises ;
 - (iii) the local income tax ;
(hereinafter referred to as "Chinese Tax").
- (b) in India :
 - the income-tax including any surcharge thereon ;
(hereinafter referred to as "Indian tax").

4. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws within a reasonable period of time after such changes.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "China" means the People's Republic of China; when used in geographical sense, means all the territory of the People's Republic of China, including its territorial sea, in which the Chinese laws relating to taxation apply, and any area beyond its territorial sea within which the People's Republic of China has sovereign rights of exploration for any exploitation of resources of the sea-bed and its sub-soil and superjacent water resources in accordance with international law ;
- (b) the term "India" means the territory of the Republic of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian Law and in accordance with international law ;
- (c) the term "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean China or India as the context requires ;
- (d) the term "tax" means Chinese tax or Indian tax, as the context requires ;
- (e) the terms "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States ;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes ;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State ;
- (h) the term "nationals" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State ;
- (i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State ;
- (j) the term "competent authority" means, in the case of China, the State Administration of Taxation or its authorized representative, and in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorized representative.

2. As regards the application of this Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the contexts otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which this Agreement applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of head office or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests) ;
- (b) If the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode ;
- (c) If he has a habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national ;
- (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its head office is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources ;
- (g) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others ;
- (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on ;
- (i) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources, but only if so used for a period of more than 183 days ;
- (j) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (together with other such sites, projects or activities, if any) continue for a period of more than 183 days ;

- (k) the furnishing of services other than technical services as defined in Article 12 (Royalties and Fees for Technical Services) by an enterprise of a Contracting State through employees or other personnel in the other Contracting State, but only if activities of that nature continue within that other Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days.

3 Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise ;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose storage, display or delivery ;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise ;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 5 apply—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, has and habitually exercises an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 3 which, if exercise through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable

property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

The provisions of this paragraph shall, however, not apply if the enterprise proves that the above activities could not have been undertaken by the permanent establishment or have no relation with the permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. Insofar as the tax law of a Contracting State provides with respect to a specific business activity that the profits to be attributed to a permanent establishment are to be determined on the basis of a deemed profit, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from applying the those provisions of its law provided that the result is in accordance with the principles contained in this Article.

4. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere in accordance with the provisions of tax law of that Contracting State.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of paragraphs 1 to 5, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise which is a resident of a Contracting State from the operation by that enterprise of ships or aircrafts in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircrafts in international traffic shall mean profits derived by an enterprise described in paragraph 1 from the transportation by sea or air respectively of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of ships aircraft including :

- (a) the sale of tickets for such transportation;
- (b) the rental of ships or aircraft connected with such transportation; and
- (c) income from use, maintenance or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) operated in international traffic.

3. For the purposes of this Article, interest on funds directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits described in this Article, and the provisions of Article 11 (interest) shall not apply in relation to such interest.

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where :—

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that Contracting State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State, and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims,

participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State.

Article 11 INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and derived by the Government of the other Contracting State, a political subdivision, a local authority and the Central Bank thereof or any financial institution wholly owned by that Government or by any other resident of that other Contracting State with respect to debt-claims indirectly financed by the Government of that other Contracting State, a political subdivision, a local authority and the Central Bank thereof or any financial institution wholly owned by that Government shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is the Government of that Contracting State, a political subdivision, a local authority thereof or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest whether he is a resident of a

Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payment of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark design or model, plan secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means any payment for the provision of services of managerial, technical or consultancy nature by a resident of a Contracting State in the other Contracting State, but does not include payment for activities mentioned in paragraph 2(k) of Article 5 and Article 15 of the Agreement.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein; and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is the Government of that Contracting State, a political subdivision, a local authority thereof or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for

technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article, arising in a Contracting State, may be taxed in that Contracting State.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State except in one of the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State;
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in the taxable year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- (a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the taxable year concerned; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contracting State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 17

ARTISTS AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived by entertainers or sportspersons who are residents of a Contracting State from the activities exercised in the other Contracting State either as a part of cultural exchange between the Contracting States or supported wholly or substantially from the public funds in either of the Contracting States or political sub-divisions or local authorities thereof, shall be exempt from tax in that other Contracting State.

Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions, annuity and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions, annuity paid and other similar payments made by the Government of a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof under a public welfare scheme of the social security system of that Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

Article 19

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICES

1. (a) Remuneration, other than pension, paid by the Government of a Contracting State or a political sub-division or local authority thereof to an individual in respect of services rendered to the Government of that Contracting State or a

political sub-division or a local authority thereof, in the discharge of functions of a governmental nature, shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other Contracting State and the individual is a resident of that other Contracting State who :

- (i) is a national of that other Contracting State ; or
- (ii) did not become a resident of that other Contracting State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds to which contributions are made by the Government of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to the Government of that Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other Contracting State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by the Government of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. An individual who is, or immediately before visiting a Contracting State was, a resident of the other Contracting State and is present in the first-mentioned Contracting State for the primary purpose of teaching, giving lectures or conducting research at a university, college, school or educational institution or scientific research institution approved by the Government of the first-mentioned Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State, for a period of three years from the date of his arrival in the first-mentioned Contracting State, in respect of remuneration for such teaching, lectures or research.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS, TRAINERS AND APPRENTICES

1. A student, business apprentice or trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education, training shall be exempt from tax in that first-mentioned State on the following payments or income received or derived by him for the purpose of his maintenance, education or training :—

- (a) payments derived from sources outside that Contracting State for the purpose of his maintenance, education, study, research or training ;
- (b) grants, scholarships or awards supplied by the Government, or a scientific, educational, cultural or other tax-exempt organization ; and
- (c) income derived from personal services performed in that Contracting State for the purpose of maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that Contracting State.

828 GI/95—4

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 23

METHODS FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In China, double taxation shall be eliminated as follows :—

- (a) Where a resident of China derives income from India the amount of tax on that income payable in India in accordance with the provisions of this Agreement, may be credited against the Chinese tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the Chinese tax on that income computed in accordance with the taxation laws and regulations of China.
- (b) Where the income derived from India is a dividend paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of China and which owns not less than 10 per cent of the shares of the company paying the dividend, the credit shall take into account the tax paid to India by the company paying the dividend in respect of its income.

2. In India, double taxation shall be eliminated as follows :—

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in China, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income-tax paid in China whether directly or by deduction. Such deductions shall not, however, exceed that part of the income-tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in China.

3. The tax paid in a Contracting State mentioned in paragraphs 1 and 2 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the legal provisions concerning tax reduction, exemption or other tax incentives of the Contracting States for the promotion of economic development.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any recruitment connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions.

3. Where a Contracting State charges the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned Contracting State at a rate of tax which is different from that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, it shall not be construed as discrimination under this Article.

4. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and deductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

5. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State subject to the provisions of domestic laws of that Contracting State.

6. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

7. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 4, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the provisions of this Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of paragraphs 2 and 3. When it seems advisable for reaching agreement,

representatives of the competent authorities of the Contracting States may meet together for an oral exchange of opinions.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement, in particular for the prevention of evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (order public).

Article 27

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which diplomatic notes indicating the completion of internal legal procedures necessary in each country for the entry into force of this Agreement have been exchanged. This Agreement shall have effect:

- (a) in China, in respect of income arising in any taxable year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which this Agreement enters into force;
- (b) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which this Agreement enters into force.

Article 29

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give written notice of termination to the other Contracting State through the diplomatic channels. In such event this Agreement shall cease to have effect:

- (a) in China, in respect of income arising in any taxable year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given ;
- (b) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at New Delhi on this eighteenth day of July one thousand nine hundred and ninety four in the Hindi, Chinese and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

Sd/-

MANMOHAN SINGH

For the Government of the
Republic of India

Sd./- Illegible,

For the Government of the
People's Republic of China

PROTOCOL

At the signing of the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income (hereinafter referred to as "The Agreement") both sides have agreed upon the following which form an integral part of the Agreement :

1. With reference to paragraph (1d) of Article 3 :
It is understood that the term "tax" should not

include any penalty imposed for non-compliance of the laws and regulations relating to the taxes to which this Agreement applies.

2. With reference to Article 8, the exemption shall also include :

- (i) in China, the business tax ;
- (ii) in India, any tax similar to the business tax in China which may be imposed in India after signing of the Agreement.

3. With reference to Article 26 :

The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the information or documents which shall be necessarily furnished on a routine basis.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at New Delhi on this eighteenth day of July one thousand nine hundred and ninety four in the Hindi, Chinese and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

Sd/-

MANMOHAN SINGH,

For the Government of the
Republic of India.

Sd./- Illegible,

For the Government of the
People's Republic of China.

[Notification No. 9747/95-F. No. 503/5/93-FTD]
V. B. SRINIVASAN, Jt. Secy.

